(d) The Social Welfare Department of Government of National Capital Territory Delhi expressed the desire to get the biscuits tested in a Government laboratory.

(e) Super Bazar has reported that all goods, particularly, edible items sold in Super Bazar are tested for their quality at pre-purchase and post-purchase stage before these are sent to the sale counters.

(f) and (g) From January, 1993 to December, 1993, 7370 samples were tested, out of which 1078 were rejected on account of being sub-standard. A statement indicating the details is at the statement.

Statement

Total Number of Samples Analysed in the Laboratory during the Period January 1993 to December 1993

Month	Total	Rejected
January . .	728	179
February . .	623	65
March . .	624	64
April . .	657	62
May . .	614	91
June . .	632	99
July . .	611	44
August .	574	112
September . .	575	100
October . .	592	73
November .	504	48
December . .	636	141
TOTAL .	7,370	1078

This includes Pulses, Cereals, Atta, Spices, Sugar, Salt, Dry fruits, Papad, Namkeen, Canned products, Milk & Milk products, Toiltries, Polythene Disinfectants, Deodarants, Cosmetics.

कोयले की ढुलाई से प्रभावित सड़कों को सुदृढ़/चौड़ा किया जाना

@1845. **श्री जगन्नाथ सिंह :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982 के दौरान केन्द्रीय सरकार के कोयला मन्त्रालय को, मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग से सड़कों को जिनकी लम्बाई 2950 कि०मी० है और जो कोयले की ढुलाई से प्रभावित हुई हैं, सुदृढ़ और चौड़ा करने हेतु 200 करोड़ रुपये का प्राक्कलन (एस्टीमेट्स) वित्तीय स्वीकृति के लिए प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त प्रस्तावों के लिए कब तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार से मई, 1982 में 202.99 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से सड़कों को चौड़ा करने तथा सुदृढ़ करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उन्हें, अनुमानों को 1985 में अद्यतन करने के लिये कहा गया था। मई, 1986 में संशोधन अनुमान प्राप्त हुए थे। राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य की सड़कों के निर्माण की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है तथा राज्य सरकारों द्वारा अपने आन्तरिक स्रोतों से निधियां जुटाने के अतिरिक्त सम्बन्धित राज्य कोयला उत्पादन पर रायल्टी तथा अन्य कर लगाकर यथेष्ट मात्रा में राजस्व एकत्र करती हैं इसलिए उन्हें स्वयं ही कोयला धारी क्षेत्र में स्थित सड़कों सहित सड़कों के निर्माण के लिए निधियां जुटाने चाहिएं।

गुजरात में कोयले की मांग और पूर्ति

1846. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की गुजरात राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कोयले की मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिये 1994-95 के

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न सं० 1241, 2-3-1994 से स्थानांतरित।